**Problems faced by Agarbatti Industries**

2930. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SHIVCHARAN SINGH:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations from the Agarbatti Industry in Karnataka and other States, about the scarcity and difficulties, faced by them in procuring the wood required for manufacture of agarbattis arising from the recent Supreme Court judgement banning the collection of wood from the forest;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to help the industry out of the crisis?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir.

(b) Representations were received from Government of Karnataka & Tripura. Various affected parties have also filed interlocutory applications before the Hon'ble Supreme Court of India.

(c) Supreme Court vide interim order dated 4.3.1997 have clarified that interim order dated 12.12.1996 would not apply to bambo, which is one of the basic raw materials for agarbatti sticks.

**Supreme Court judgement on Prawn Culture**

2931. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have complied with and implemented the tenors of the Supreme Court's judgement, dated the 11th February, 1996 in writ petition No. 561 of 1994, concerning prawn culture; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDING SOZ): (a) and (b) In compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court on December 11, 1996, Government have constituted an Aquaculture Authority under Section 3(3) of the Environment (Protection) Act, 1986. This Authority will deal with all issues relating to shrimp culture industry in the coastal areas of the country.

**मध्य प्रदेश में पर्यावरण क्लबों का स्थापित किया जाना**

2932. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री रामजीलाल:**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कुछ राज्य सरकारों विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों और कालेजों में पर्यावरण क्लब स्थापित करने और जिला एवं राज्य स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण समितियां गठित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

**पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़)**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**Number of Deaths due to Air Pollution**

2933. SHRI LAKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item, captioned, 'diseases caused by pollution

are on the rise, warn doctors', published in "The Hindustan Times", dated 30th January, 1997;

(b) if so, the number of deaths occurred in the country because of air pollution during the last three years, year-wise and State-wise;

(c) whether ozone level is measured in India; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. Owing to increase in levels of pullution in the ambient air due to large scale increase in vehicles and industrial complexes leading to atmospheric pullution, there could be an increase in health related problems. However, no conclusive statistical data is available on morbidity and mortality rates.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

**मध्य प्रदेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का विनियमन**

2934. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 24.10.80 तक वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का विनियमन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दी जाएगी?

**पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़):** (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मध्य प्रदेश सरकार से वन भूमि पर अवैध कब्जों के नियमितीकरण हेतु तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की स्थिति नीचे दी गई है:

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | जिला | क्षेत्र (हेक्टेयर) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश | सभी जिले | 1,03,000.00 | राज्य सरकार ने 2.73 लाख हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्तता मापदंड के आधार पर उपयुक्त पाए गए अवैध काबिजों के पक्ष में जुलाई, 1990 में 1.03 लाख हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण का अनुमोदन किया गया था। |
| 2. | मध्य प्रदेश | सभी जिले | 1,77,938.431 | राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए और |
| 3. | मध्य प्रदेश | खार गांव | 3,773.349 | इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। |

(ग) इस मंत्रालय में पूर्ण ब्यौरे और स्थल निरीक्षण की रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात गुण दोष के आधार पर प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।

**Scheme to create City Forest**

2935. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) in how many States/Union Territories scheme to create city forest is being implemented;

(b) how much funds have been earmarked for this purpose;

(c) whether any such scheme is being implemented in Orissa; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (d) The informaiton is being collected and will be laid on the Table of the House.